



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 256]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 13, 2007/फाल्गुन 22, 1928

No. 256]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 13, 2007/PHALGUNA 22, 1928

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

(एफ सी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2007

प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (संशोधन) अधिसूचना, 2007

का.आ. 354(अ).—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रिट याचिका (सिविल) 1995 की संख्या 202 में आई ए संख्या 556 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 29 अक्टूबर, 2002 के आदेश के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 5-1/98 एफ सी के तहत प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (जिसे इसके बाद कम्पा कहा जाएगा) का गठन किया गया था इसे भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में दिनांक 23 अप्रैल, 2004 की संख्या का.आ. 525(अ) के तहत प्रकाशित किया गया था;

और दिनांक 28 नवम्बर, 2006 को भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के दिनांक 26 सितम्बर, 2005 के आदेशों के तहत दिनांक 23 अप्रैल, 2004 की कम्पा अधिसूचना में कतिपय संशोधन करने के आदेश दिए हैं;

और इसके अतिरिक्त पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 28 नवम्बर, 2006 और 26 सितम्बर, 2005 के आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय सरकार दिनांक 23 अप्रैल, 2004 की कम्पा अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है :

1. इस अधिसूचना को "प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (संशोधन) अधिसूचना, 2006" कहा जाएगा।
2. "कार्यकारी निकाय" के गठन से संबंधित दिनांक 23 अप्रैल, 2004 की कम्पा अधिसूचना के पैरा 2.2 में निम्नलिखित उप-पैरा जोड़ा जाए नामतः :-
"(viii) दो विशेषज्ञ, वानिकी और वन आर्थिक विकास के क्षेत्र से एक-एक सदस्य"
3. "कोष के प्रबंधन" से संबंधित दिनांक 23 अप्रैल, 2004 की कम्पा अधिसूचना के पैरा 6.3 में उप-पैरा (iv) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात् :-
"(iv) कम्पा दोहरी प्रणाली के आधार पर सामूहिक लेखा-जोखा तैयार करेगा और इसके लेखा-जोखा की भारत के महालेखा निरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की जाएगी।"
4. "कोषों के वितरण" से संबंधित दिनांक 23 अप्रैल, 2004 की कम्पा अधिसूचना के पैरा 6.4 में उप-पैरा (v) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात् :-
"(v) कम्पा में किसी राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र से पैरा 6.2 के अनुसार प्राप्त धन तथा कम्पा द्वारा इसकी स्थापना, मानीटरिंग और प्रो-रेटा आधार पर मूल्यांकन के लिए खर्च को घटाने के बाद अर्जित आय साधारणतः उस विशिष्ट राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र द्वारा प्रयोग की जाती है तथापि सीमापार वानिकी और/अथवा विशिष्ट राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र में गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के वनेतर प्रयोग के पर्यावरणीय निहितार्थ, यदि "कम्पा" द्वारा उचित और आवश्यक

समझा जाता है तब विशिष्ट राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र से प्राप्त धन को साथ के राज्य (राज्यों) अथवा संघ शासित क्षेत्र (क्षेत्रों) द्वारा कम्पा द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित अनुपात में प्रयोग किया जा सकता है ताकि वन और/अथवा पर्यावरण पर पार-सीमा प्रतिकूल प्रभाव (प्रभावों) को कम किया जा सके।”

5. “अन्य कार्यों” से संबंधित दिनांक 23 अप्रैल, 2004 की कम्पा अधिसूचना के पैरा 6.6 के उप-पैरा (i) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए नामतः :-

“(i) कम्पा, प्रतिपूरक वनीकरण को करने के लिए विशेषतः बड़े सार्वजनिक उपक्रमों को शामिल करते हुए, जिन्हें उनकी परियोजनाओं के लिए अक्सर वनभूमि की आवश्यकता होती है, सी ई सी के परामर्श और जहाँ तक संभव हो सहमति से और साथ ही भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय की अनुमति के साथ कार्य विशेष वाहन स्थापित करेगा।”

[फा. सं. 5-2/2006-एफ सी]

अंसार अहमद, वन महानिरीक्षक

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(F. C. Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2007

Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (Amendment) Notification, 2007

S.O. 354(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), and in pursuance of the Hon'ble Supreme Court's order dated 29th October, 2002 in I.A. No. 566 in Writ Petition (Civil) No. 202 of 1995, Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (hereinafter referred to as 'CAMPA') was constituted by the Central Government *vide* Notification No. 5-1/98-FC of the Ministry of Environment and Forests, Government of India, which was published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India (Extraordinary) *vide* S.O. 525(E), dated 23rd April 2004;

And whereas, *vide* order dated 28th November, 2006, the Hon'ble Supreme Court of India directed for making certain amendments in the CAMPA Notification dated 23rd April, 2004 in terms of the Supreme Court's order dated 26th September, 2005;

And therefore, in exercise of the power conferred by Sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), and in compliance of the Hon'ble Supreme Court's orders dated 28th November, 2006 and 26th September, 2005, the Central Government hereby makes the following amendments in the CAMPA Notification dated 23rd April, 2004 :

1. This Notification may be called the 'Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (Amendment) Notification, 2007'
2. In para 2.2 of the CAMPA Notification dated 23rd April, 2004 concerning constitution of 'Executive Body', following sub-para may be added, namely :—
“(viii) Two Experts, one each in the fields of Forestry and Forest Economy Development —Members.”
3. In para 6.3 of the CAMPA Notification dated 23rd April, 2004, concerning 'Management of the Fund', for sub-para (iv), following shall be substituted, namely :—
“(iv) The CAMPA shall have Corporate Accounting based on double entry system, and auditing of its accounts shall be conducted by the Comptroller and Auditor General (CAG) of India.”
4. In para 6.4 of the CAMPA Notification dated 23rd April, 2004, concerning 'Disbursement of Funds', for sub-para (v), following shall be substituted, namely :—
“(v) The monies received in CAMPA from a State or Union Territory as per para 6.2, and the income earned thereon after deducting the expenditure incurred by CAMPA on its establishment, monitoring and evaluation on a pro-rata basis, shall ordinarily be used only in that particular State or Union Territory. However, in cases of trans-boundary forestry and/or environmental implication(s) of diversion of forest land for non-forestry purposes in a particular State or Union Territory, if found expedient and necessary by CAMPA, the monies received from that particular State or Union Territory may also be used, in the proportion as determined by CAMPA for the purpose, in the adjoining State(s) or Union Territory(ies) to mitigate trans-boundary adverse impacts on forest and/or environment.”
5. In para 6.6 of the CAMPA Notification dated 23rd April, 2004, concerning 'Other Functions', for sub-para (i), following shall be substituted, namely :—
“(i) The CAMPA shall establish Special Purpose Vehicles (SPV) for undertaking Compensatory Afforestation, especially by involving large Public Sector Undertakings which frequently require forest land for their projects, in consultation and as far as possible, with concurrence of the CEC, and with the permission of the Hon'ble Supreme Court of India.”

[F. No. 5-2/2006-FC]

ANSAR AHMED, Inspector General of Forests